Setting up of Pig-Iron Plant in Orissa

256. SHRI JAGADISH JANI: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a Pig iron plant in Orissa:

(b) whether the proposed plant would be set up by the Government of India or by the State Government in collaboration with some private sector company;

(c) the details of the proposal received by Government in this regard; and

(d) the site selected for location of the plant?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR): (a) and (b) The Government of India have no proposal to set up a pig iron plant in Orissa. M/s. Industrial Promotion and Investment Corporation of Orissa Limited (IPICOL), a Government of Orissa undertaking have, however, been granted a registration No. 952(87) DLR dated 10-7-1987 for setting up of an industrial undertaking for manufacture of 1,00,000 tonnes per annum of pig iron of various grades at Paradeep, District Cuttack. IPICOL have reported that they have signed a memorandum of understanding on 2-5-1988 with M/s. Dalmia Cement (Bharat) Limited to implement the project and also concluded a joint venture agreement with them on 12-9-1988.

(c) No proposal about association of M/s. Dalmia Cement (Bharat) Limited with the project has been received.

(d) The location of plant is at Paradeep. At the time of making the application for an industrial licence, IPICOL had stated that the project would be set up close to port area.

बिहार में पम्पसेटों की सप्लाई

257. **श्री रामनरेश यादव** : क्या कृषि मंत्री 25 मार्च, 1988 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 324 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के किन-किन जिले लघु सीमान्त कृषकों को अनुदान के रूप में बोरिंग और पम्प सेट दिए गए हैं तथा ऐसे सैटों की संख्या कितनी है तथा उनमें से ऐसे कितने पम्प सैट हरिजन जनजाति के लोगों को दिए गए हैं;

(ख) क्या इन सभी बोरिंग और पम्प सेटों का नाबार्ड अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा मौखिक रूप से सत्यापन करा लिया गया है; यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ;

(ग) क्या सरकार जांच का कार्य पूरा हो जाने तक कर्ज वसूली स्थगित करने के बारे में विचार करेगी; यदि नहीं तो उसके क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार किसानों से वसूल की गई अतिरिक्त धनराशि सूद सहित वापस करेगी; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पहले के जिस प्रश्न का जिक्र किया गया है वह 9 दिसम्बर, 1983 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2072 की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। इस प्रश्न में, उल्लिखित शिकायत विशेष रूप से दरभंगा जिले के बारे में है। राज्य सरकार के लघु सिंचाई विभाग ने 1982-83 में 60,000 ट्यूबवैल लगाने की एक योजना आरम्भ की थी, जिसमें से दरभंगा को 2500 कुओं का लक्ष्य आवंटित किया गया था। प्राप्त सूचना के अनुसार दरभंग, जिले में वास्तविक उपलब्धि लगभग